योजना का सारांश (जून 2026)

1. नक्सल मुक्त भारत : एक ऐतिहासिक उपलब्धि

परिचय

वामपंथी उग्रवाद को एक वैचारिक-सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाता है जिससे निपटने लिए समन्वित बल, विकास और पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

विचारधारा, भौगोलिक स्थिति और शासन में शून्यता

- माओवादी बंदूक-आधारित विचारधारा ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखा, न कि आदिवासी अधिकारों, न्याय या विकास का।

- बस्तर की 35% साक्षरता दर, सहरसा (33%) और बलिया (31%) के समान थी, जिससे केवल गरीबी को कारण मानने वाली व्याख्या कमजोर पड़ती है।
- घने जंगलों, नदियों एवं झरनों ने राज्य के अभियानों को सीमित कर दिया, जिससे माओवादियों को लगातार भूभाग पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली।
- माओवादियों ने बैंकों, सड़कों और स्कूलों को बंद कर दिया और सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जनताना टैक्स के तौर पर 240 करोड़ रुपये वसूले।
- रेड कॉरिडोर 12 राज्यों तक फैला था, जो देश के 17% भूभाग और लगभग 20 करोड़ लोगों को शामिल करता था; इस दौरान लगभग 20,000 युवा और 3,500 सुरक्षाकर्मी मारे गए।

2014 के बाद की नीति और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण

- वर्ष 1970 से 2004 के बीच नीति की अस्पष्टता के कारण माओवादी संगठन मज़बूत हुए, जिसमें 2004 में सीपीआई (माओवादी) का गठन भी शामिल है।
- वर्ष 2014 के बाद सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), राज्य पुलिस, खुफिया तंत्र और वित्तीय नेटवर्क को लक्षित करने वाली प्रणाली को एकीकृत किया गया।
- 20 अगस्त 2019 की रणनीति का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल-मुक्त बनाना था।
- प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर मात्र 2 रह गई, जबकि प्रभावित पुलिस थानों की संख्या 350 से घटकर 7 रह गई।
- सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने के लिए 596 नए थाने, 406 सीआरपीएफ कैंप, 68 हेलीपैड, 400 वाहन और 5 अस्पताल स्थापित किए गए।
- वर्ष 2024 से 2026 के दौरान चलाए गए अभियानों में 606 माओवादी मारे गए, 2,218 गिरफ्तार किए गए तथा 4,839 ने आत्मसमर्पण किया।

प्रौद्योगिकी, विकास और पुनर्एकीकरण

- ड्रोन निगरानी, उपग्रह चित्रण और एआई-आधारित तकनीकों के उपयोग से ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिससे कर्रेगुट्टालू शिविर में मौजूद लगभग 400-500 कैडरों का विघटन हुआ।
- केंद्रीय पोलित ब्यूरो के 21 सदस्यीय नेतृत्व का पतन हो गया, जिसके बाद दंडकारण्य की 37 सदस्यीय राज्य समिति को पूरी तरह भंग कर दिया गया।
- लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत से 17,589 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, जिनमें से 12,000 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हुआ। साथ ही 5,000 टावरों के माध्यम से 6,000 गाँवों तक नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुँचाई गई।
- समावेशन के तहत 1,804 बैंक शाखाएँ, 1,321 एटीएम, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट तथा 6,025 डाकघर स्थापित किए गए।
- मानव सेवाओं के अंतर्गत 240-बेड वाला जगदलपुर अस्पताल, 259 स्कूल, 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), 49 कौशल विकास केंद्र (NDC) और 1 करोड़ रुपए तक की अनुदान योजनाएँ लागू की गईं।
- पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को 5 लाख रुपये की सहायता, 10,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। साथ ही बस्तर ओलंपिक्स-पांडुम जैसे आयोजनों में लगभग 5.5 लाख आदिवासी और 1.2 लाख कलाकारों की भागीदारी दर्ज की गई।

निष्कर्ष

नक्सल-मुक्त मॉडल सुरक्षा दबाव, विकासात्मक सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्वेच्छा से मुख्यधारा में वापसी के संयोजन पर आधारित है जिसका उद्देश्य संवैधानिक शासन की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना है।

2. संघर्ष से प्रगति की ओर

परिचय

छत्तीसगढ़ के बस्तर में हो रहा बदलाव, सशस्त्र नक्सलवाद को रोकने के प्रयासों को स्थानीय सुरक्षा, विकास और पुनर्वास-आधारित स्वीकार्यता से जोड़ता है।

संघर्ष, स्थानीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी

- लगभग चार दशकों तक नक्सलवाद ने बस्तर में सड़कों, बिजली, पानी, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुँच को बाधित किया है।
- डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के केवल 10-15% सदस्य आत्मसमर्पित नक्सली थे, जबकि परिचालन का मुख्य आधार बस्तर के स्थानीय युवा रहे।
- केंद्रीय सीएपीएफ शिविरों ने दूरस्थ क्षेत्रों को सुरक्षित किया, जिससे संचालन और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी संभव हो सकी।
- ड्रोन निगरानी, रेडियो ट्रैकिंग और एजेंसियों के समन्वय ने सुरक्षा बलों को तकनीकी बढ़त प्रदान की।
- आईटीबीपी, एनएसजी, एनटीआरओ, डीआरडीओ और इसरो के सहयोग से जंगलों में बिना किसी नुक्सान के सटीक अभियान चलाने में सफलता मिली।

विकास और शासन की सेवाओं का विस्तार

- तेंदू के पत्तों को निजी ठेकेदारों से मुक्त कराया गया, जिससे नक्सली फंडिंग में कमी आई और सार्वजनिक लाभ में सुधार हुआ।
- नियाद नेल्ला नार पहल के तहत 144 ग्राम पंचायतों में 25 व्यक्तिगत और 18 सामुदायिक कार्यक्रमों को एकीकृत किया।

- 99 सुरक्षा शिविरों के माध्यम से 500 से अधिक गाँवों तक सरकारी सेवाएँ पहुँचाई गई और ग्राम पंचायतों के जरिए लाभार्थियों को उनके अधिकार उपलब्ध कराए गए।
- बस्तर के 87% गाँवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुँचा और 38 बस रूटों से सड़क संपर्क बेहतर हुआ।
- एनसीईआर (NCAER) के अध्ययन के अनुसार 93% स्कूल पहुँच, 97% मध्यान्ह भोजन उपलब्धता, 97% आंगनवाड़ी कवरेज और 89% आयुष्मान भारत योजना कवरेज दर्ज किया गया।
- पूवर्ती के 2024 में स्थापित सीआरपीएफ शिविर ने पहली बार मतदान, सड़कों, गुरुकुल शिक्षा, बिजली और बिहान प्रशिक्षण को संभव बनाया।

पुनर्वास और सामाजिक मुख्यधारा में वापसी

- एक नई पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों का समुदायों के बीच स्वागत किया गया, जो संवैधानिक जीवन में उनकी वापसी का संकेत था।
- रेड कार्पेट केंद्रों ने 15, 20 और 25 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए प्रशिक्षण, दस्तावेज, सर्जरी और पहचान बहाली की सुविधा प्रदान की।
- 55 पीड़ितों ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह के साथ नक्सली हिंसा के संबंध में गवाहों के बयान साझा किया।
- 2024-2025 के दौरान बस्तर ओलंपिक में भाग लेने वालों की संख्या 1.65 लाख से बढ़कर 3.91 लाख हो गई; डोडा विजय और मुचाकी राणावती ने समाज में वापसी की मिसाल प्रस्तुत की।
- बस्तर पांडुम 2025-2026 के माध्यम से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया, जबकि लक्ष्मू पोयाम और पूलमाथी मंडावी ने पांडुम कैफे के जरिए अपने जीवन का सफल पुनर्निर्माण किया।

निष्कर्ष

बस्तर का रूपांतरण एक सुरक्षा-विकास मॉडल प्रस्तुत करता है जहाँ स्थानीय विश्वास, सेवा वितरण और पुनर्वास से शासन व्यवस्था बहाल होती है।

3. नक्सल-मुक्त भारत : एक रणनीतिक बदलाव

परिचय

नक्सल-मुक्त भारत एक समन्वित शासनप्रबंधन प्रस्तुत करता है जहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पेशेवर सुरक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता उग्रवाद को परावर्तित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत और संस्थागत परिवर्तन

- नक्सली चुनौती के लिए सुरक्षा, शासन, बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी सेवाओं के संपूर्ण सरकारी एकीकरण की आवश्यकता थी।
- गृह मंत्रालय ने शून्य-सहिष्णुता रणनीति का नेतृत्व किया, जबकि राज्यों ने संवैधानिक कानून-व्यवस्था के जनादेश के तहत अग्रिम पंक्ति की जिम्मेदारी बरकरार रखी।
- वर्ष 2015 की कार्ययोजना में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध 'ट्रेस, टार्गेट और न्यूट्रलाइज' रणनीति को विकास और सुरक्षा के समन्वय के साथ लागू किया गया।
- समाधान (SAMADHAN) रणनीति ने कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, खुफिया जानकारी, प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण पर रोक और क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजनाओं को आपस में एकीकृत किया।
- मार्च 2026 तक, सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी और एफओबी के माध्यम से अधिकांश सीपीआई (माओवादी) नेतृत्व को निष्क्रिय कर दिया था।

अभियानों में तेजी और सुरक्षा क्षमता

- 350 से अधिक सुरक्षा शिविरों के माध्यम से सीआरपीएफ-कोबरा, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, डीआरजी, सी-60, एसओजी और जगुआर जैसी विभिन्न सुरक्षा इकाइयों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया।
- ऑपरेशन डबल बुल 8 फरवरी 2022 को शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत 12 दिनों में 10 मुठभेड़, नौ गिरफ्तारियाँ और आईईडी को निष्क्रिय किया गया।
- वर्ष 2025 में ऑपरेशन ऑक्टोपस और बुरा पहाड़ ने नक्सली नेतृत्व को निशाना बनाया, जिसके तहत 300 लोगों को निष्क्रिय कर दिया गया और 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
- 21 में से सीपीआई (माओवादी) के 12 शीर्ष नेताओं को निष्क्रिय कर दिया गया, सात ने आत्मसमर्पण कर दिया, एक को गिरफ्तार कर लिया गया; एक शीर्ष नेता अभी भी सक्रिय है।
- वर्ष 2016 से मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी), 15 संयुक्त कार्यबल (जेटीएफ) और 2 मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप (एमडीजी) के माध्यम से खुफिया समन्वय को सुदृढ़ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 40 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि जब्त की गई।
- एसआरई में 155 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 3,371 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि एसआईएस के अंतर्गत 246 पुलिस थानों के लिए 371 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

विकास और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण

- सड़क, टेलीकॉम, शिक्षा, बैंकिंग और कौशल विकास ने प्रभावित जिलों में भर्ती की स्थितियों को सीधे तौर पर कमजोर किया है।
- प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में 11 रह गई; सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 36 से घटकर छह हो गई।
- कैंपों ने दूर-दराज की आबादी के लिए सड़कों, मतदान केंद्रों, स्कूलों, मोबाइल टावरों और स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित किया।

- अशांत क्षेत्रों में हुए चुनावों ने बेहतर प्रशासन, कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों और लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाया।
- बचे हुए इलाकों और मुश्किल भौगोलिक स्थितियों में लगातार सतर्कता, विकास और संस्थागत मज़बूती की जरूरत है।
- नक्सल-मुक्त भारत सहकारी संघवाद और राष्ट्रीय संकल्प के जरिए रेड कॉरिडोर को ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहा है।

निष्कर्ष

यह बदलाव दर्शाता है कि सुरक्षा तभी सफल होती है जब उसे सुशासन, विकास और सामुदायिक विश्वास के साथ जोड़ा जाता है।

4. वामपंथी उग्रवाद उन्मूलन के लिए सरकार का समग्र दृष्टिकोण

परिचय

भारत की वामपंथी उग्रवाद (LWE) के प्रति प्रतिक्रिया केवल पुलिस-आधारित कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि समय के साथ यह संपूर्ण-सरकार (Whole-of-Government) दृष्टिकोण में विकसित हुई। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सुरक्षा, विकास और समुदाय के विश्वास को एक साथ जोड़कर वामपंथी उग्रवाद के स्थायी समाधान का प्रयास किया गया।

ऐतिहासिक जड़ें और रणनीतिक बदलाव

- नक्सलबाड़ी के 1967 के विद्रोह से सशस्त्र माओवाद की शुरुआत हुई; 1969 में चारु मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल के नेतृत्व में सीपीआई (एमएल) का गठन हुआ।
- 1970 के दशक में पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से माओवादी आंदोलन कमजोर पड़ा, लेकिन 1980 के दशक में पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) के पुनरुत्थान के साथ इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से अन्य राज्यों तक होने लगा।
- माओवादियों ने आदिवासी क्षेत्रों में जनताना सरकार, अवैध वसूली और कंगारू अदालतों के माध्यम से लोगों पर दबाव बनाकर समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास किया।
- इनका विस्तार घने जंगलों, कमजोर शासन-व्यवस्था और खराब कनेक्टिविटी वाले इलाकों में हुआ, न कि सिर्फ गरीबी या पिछड़ेपन के कारण।
- वर्ष 2015 की कार्ययोजना में सुरक्षा, विकास, अधिकारों और धारणा प्रबंधन (perception management) के माध्यम से सरकार के सभी विभागों के बीच समन्वय की नीति अपनाई गई।

सुरक्षा क्षमता और परिचालन परिणाम

- राज्य पुलिस ने माओवादी-विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया, जबकि गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान तथा विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्यों को सहयोग प्रदान किया।
- 2009 से 2025 के बीच सुरक्षा शिविरों (Security Camps) की संख्या 27 से बढ़कर 837 हो गई। इसी अवधि में 121 बटालियन, 400 कंपनियाँ तथा 1,143 बस्तरिया (Bastariya) भर्ती तैनात किए गए।
- सुरक्षा संबंधी अवसंरचना योजना (SIS) के तहत 706 पुलिस स्टेशनों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 660 का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं SRE-ACALWEM योजना के अंतर्गत ₹3,756.38 करोड़ तथा ₹1,249.38 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई।
- संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) ने अंतरराज्यीय कमियों को दूर किया; ब्लैक फॉरेस्ट में 10,000 कर्मियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 31 माओवादियों को निष्क्रिय कर दिया गया।
- 2014-2025 के दौरान हिंसा की घटनाएँ 870 से घटकर 234 रह गई, मौतें 222/88 से घटकर 64/36 हो गई, जबकि बरामदगी 548 से बढ़कर 1,190 और माओवादियों को मार गिराने की संख्या 63 से बढ़कर 364 हो गई।
- 2010-2025 के दौरान LWE (वामपंथी उग्रवाद) की घटनाएँ 1,936 से घटकर 234 और मौतें 1,005 से घटकर 100 रह गई, जो 88%-90% की कमी को दर्शाता है।

विकास, अधिकार और सामुदायिक ट्रस्ट

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 11,958 किमी सड़कें और 691 पुल निर्मित किए; साथ ही 11,611 किमी राज्य-मानक सड़कों और बीआरओ परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- सड़कों का घनत्व 30% और राजमार्गों का घनत्व 80% बढ़ गया साथ ही, दल्ली राजहरा-रावघाट, रावघाट-जगदलपुर और दंतेवाड़ा-मनुगुरु रेल परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
- 9,000 से अधिक टावरों के माध्यम से 96% कनेक्टिविटी प्रदान की गई। इसके साथ ही 1,804 शाखाओं, 1,321 एटीएम, 74,720 संवाददाताओं और 5,731 डाकघरों ने वित्तीय और डाक सेवाओं तक पहुँच का विस्तार हुआ।
- शिक्षा विभाग ने 259 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, 179 संचालित विद्यालय, 48 आईटीआई और 61 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए हैं।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के अस्पतालों ने 77,000 से अधिक स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कीं। वहीं विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) के अंतर्गत 2017 से अब तक ₹4,097.47 करोड़ जारी किए गए, जिनसे 15,000 से अधिक विकास परियोजनाएँ संचालित की गई।
- वन अधिकारों के माध्यम से 1.8 मिलियन स्वामित्व अधिकार प्रदान किये गए। साथ ही समुदाय-केंद्रित पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं को मुख्यधारा में शामिल किया।

निष्कर्ष

वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के प्रयासों से सुरक्षा के मामले में जो लाभ मिलते हैं, वे तब स्थायी होते हैं जब उन्हें विकास, अधिकारों के वितरण और समुदाय की भागीदारी के साथ जोड़ा जाता है।

5. बस्तर ओलंपिक

परिचय

बस्तर ओलंपिक खेलों के माध्यम से शांति निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, जो संघर्ष से प्रभावित युवाओं को समावेश, आत्मविश्वास और सामुदायिक परिवर्तन की ओर ले जाता है।

खेल शांति निर्माण और सामाजिक समावेशन के रूप में

- बस्तर ओलंपिक 2025 ने 2024 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन को सामाजिक पुनरुत्थान में परिवर्तित कर दिया।
- खेलों ने अनुशासन, टीम वर्क और सम्मान को बढ़ावा दिया, जिससे नागरिकों, संस्थानों और समुदायों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण हुआ।
- इसमें भाग लेने वालों की संख्या 2024 में 1.65 लाख से बढ़कर 2025 में लगभग 3.91 लाख हो गई।
- महिलाओं की भागीदारी ने समावेशन को चिह्नित किया, जिससे संघर्ष से प्रभावित समुदायों को दृश्यता, गरिमा और व्यापक सामाजिक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ।
- नुआ बात (Nua Baat) पहल के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी, हिंसा से प्रभावित पीड़ित तथा दिव्यांग खिलाड़ी बस्तर के सभी सात जिलों से शामिल हुए।

पेशेवर निष्पादन और अवसर मार्ग

- 32 विकास खंडों में फैले 60 से अधिक खेल के मैदानों ने व्यापक पहुँच और संगठित भागीदारी को संभव बनाया।
- पारंपरिक और आधुनिक खेलों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल शामिल थे, जो राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार आयोजित किए गए।
- प्रशिक्षण पाए रेफरी, इंस्ट्रक्टर और टेक्निकल अधिकारियों ने विश्वसनीयता, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा का अनुभव बेहतर बनाया।
- मेडल, सर्टिफिकेट, आर्थिक प्रोत्साहन और स्पोर्ट्स अकादमियों ने सिर्फ दिखावे की भागीदारी से आगे बढ़कर आगे बढ़ने के रास्ते बनाए।
- यूथ आइकॉन ने स्थानीय चैंपियनों को सबके सामने लाया, जिससे खेलों में मिली सफलता लोगों को साफ दिखी, वे उससे जुड़ाव महसूस कर सके और उसे हासिल करने की प्रेरणा मिली।

मुख्यधारा में वापसी, पहचान और शासन का संबंध

- लगभग 700 आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने खेलों में हिस्सा लिया और डर के बजाय उम्मीद, एकता और विकास को चुना।
- सहभागिता ने युवाओं को अपनेपन, मान्यता और रचनात्मक पहचान प्रदान करके चरमपंथी पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर किया।
- परिवारों, नेताओं और गाँवों ने सामुदायिक स्वामित्व को मज़बूत किया, जिससे खेल स्थायी शांति के लिए एक मंच बन गया।
- ओलंपिक खेलों ने कनेक्टिविटी, शिक्षा और आजीविका संबंधी पहलों को बढ़ावा दिया, जिससे यह साबित हुआ कि केवल सुरक्षा से ही सामान्य स्थिति कायम नहीं रह सकती।
- समावेशी और मानव-केंद्रित परिवर्तन के माध्यम से बस्तर की पहचान संघर्ष क्षेत्र से प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में बदल गई।

निष्कर्ष

बस्तर ओलंपिक से पता चलता है कि खेल मतभेदों को दूर कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी शांति का समर्थन कर सकते हैं।

6. शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण

परिचय

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शांति निर्माण से जोड़ता है। साथ ही अवसर, आत्मविश्वास और राज्य के भरोसे का विस्तार करके वामपंथी उग्रवाद को कमजोर करता है।

ऐतिहासिक चुनौती और संस्थागत संरचना

- वामपंथी उग्रवाद ने गरीबी, अलगाव और अपर्याप्त शिक्षा का फायदा उठाया, जिससे कमजोर आदिवासी युवाओं को नक्सली संगठन में धकेल दिया।
- 1999 में अनुच्छेद 275(1) के तहत गुणवत्तापूर्ण जनजातीय शिक्षा का समर्थन करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू हुआ।
- 2018 की केंद्रीय क्षेत्र योजना ने ईएमआरएस को पूरी तरह से आवासीय, नि:शुल्क और राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत बना दिया।
- EMRS सुरक्षा और अवसर को संतुलित करते हुए छात्रों के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के भीतर कक्षा VI-XII की स्कूली शिक्षा प्रदान करता है।

उग्रवाद-विरोधी के रूप में शिक्षा

- शिक्षा संवैधानिक जागरूकता, रोजगार के अवसर और लोकतांत्रिक आस्था का निर्माण करती है, जिससे माओवादी विचारधारा के प्रति आकर्षण कमजोर होता है।
- आवासीय परिसर बच्चों को चरमपंथी प्रभाव से दूर रखते हैं, जिससे नियमित शिक्षा और सकारात्मक जीवन शैली के माध्यम से नक्सल भर्ती में कमी आती है।
- शिक्षकों और विद्यालय प्रशासकों की निरंतर उपस्थिति दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में राज्य की पहुँच और उपस्थिति को सुदृढ़

करती है, जिससे दूरस्थ और अलग-थलग समुदायों में विश्वास मज़बूत होता है।

- 259 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) को मंजूरी दी गई, जिनमें से 178 विद्यालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करते हैं।
- देशभर में 50,000 से अधिक आदिवासी छात्र अब सुरक्षित आवासीय परिसरों में अध्ययन कर रहे हैं।

अवसंरचना, गुणवत्ता और आकांक्षाएँ

- स्मार्ट कक्षाएँ, कंप्यूटर लैब और विज्ञान प्रयोगशालाएँ आदिवासी शिक्षार्थियों को आधुनिक और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से जोड़ती हैं।
- सभी परिसरों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करती है और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देती है।
- सीबीएसई से संबद्धता और राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षकों की गुणवत्ता और मार्गदर्शन संबंधी सहायता सुनिश्चित करती है।
- उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी-नीट की कोचिंग प्रदान करते हैं, जिससे भावी छात्रों की आकांक्षाएँ डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक बनने की ओर अग्रसर होती हैं।
- खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जनजातीय पहचान में लचीलापन, एकीकरण और गौरव का निर्माण करती हैं।
- चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पूर्व छात्र मार्गदर्शक और आदर्श की भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षा को शांति के आधारभूत ढाँचे के रूप में प्रदर्शित करता है, जो चरमपंथी भेद्यता को ज्ञान, अवसर और आशा से प्रतिस्थापित करता है।

7. नक्सल मुक्त भारत में दूरसंचार क्षेत्र का विकास

परिचय

दूरसंचार संपर्क वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति का परिचायक बन गया, जिसने सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं का वितरण और सार्वजनिक विश्वास को आपस में जोड़ दिया।

राज्य की उपस्थिति और समावेशन के रूप में संपर्क

- दशकों तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्र भौतिक रूप से दूरस्थ और डिजिटल रूप से कटे रहे, जिससे शासन, अवसरों तथा राज्य के प्रति विश्वास कमजोर हुआ।
- दूरसंचार टावरों ने दूरदराज के गाँवों में कक्षाओं, बाजारों, पेंशनों, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजनाओं, परिवारों और प्रशासनिक पहुँच को आपस में जोड़ दिया।
- डिजिटल कनेक्टिविटी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), जन धन, यूपीआई तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ पहले से वंचित समुदायों तक पहुँचाना संभव बनाया।
- संपर्क व्यवस्था ने सुरक्षा समन्वय, कानून व्यवस्था प्रबंधन और कल्याणकारी गतिविधियों को मज़बूत किया, जिससे माओवादी प्रभाव वाले शासन-शून्य क्षेत्रों को कम करने में सहायता मिली।
- डिजिटल भारत निधि (DBN), जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के नाम से जाना जाता था, ने उन क्षेत्रों में भी समावेश को प्राथमिकता दी जहाँ व्यावसायिक दृष्टि से दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराना संरचनात्मक रूप से लाभकारी नहीं था।

डीबीएन (DBN) विस्तार और एलडब्ल्यूई (LWE) क्षेत्रों में कवरेज

- वर्ष 2014 में एलडब्ल्यूई चरण-I (LWE Phase-I) के अंतर्गत 2,199 स्थानों, 2,304 दूरसंचार टावरों तथा 106 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को स्वीकृति प्रदान की गई।
- एलडब्ल्यूई चरण-I के तहत 2,290 टावर स्थापित किए गए, जिनमें छत्तीसगढ़ (491), झारखंड (808) और ओडिशा (256) में व्यापक कवरेज सुनिश्चित की गई।
- एलडब्ल्यूई चरण-II के अंतर्गत 1,216 टावर स्थापित किए गए, जिनमें छत्तीसगढ़ (476), ओडिशा (358) और आंध्र प्रदेश (195) प्रमुख रहे।
- एलडब्ल्यूई चरण-II में अन्य राज्यों में भी कवरेज का विस्तार किया गया, जिसमें महाराष्ट्र (78), झारखंड (73), मध्य प्रदेश (24) और तेलंगाना (11) शामिल हैं।
- डीबीएन परियोजनाओं में कुल 5,863 टावर जोड़े गए, जिनमें ओडिशा के 2,092, आंध्र प्रदेश के 1,456 और झारखंड के 807 टावर शामिल हैं।
- 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 1,275 एलडब्ल्यूई स्थानों तक स्वदेशी कवरेज का विस्तार किया।

शासन, सुरक्षा और स्थानीय परिवर्तन

- दूरसंचार टावरों ने पीएमआईएस (PMIS), संचार मंत्रालय (MoC) के डैशबोर्ड तथा कैबिनेट सचिव द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं को सशक्त बनाया, जिससे डेटा-आधारित क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित हुई।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित टावरों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया और एफआरए, एफसीए, ईआईए, सामाजिक लेखापरीक्षा और सीएएमपीए के तहत सुरक्षा उपाय लागू किए गए।
- डीबीएन टावर अब 30 लाख उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं, जिनमें से 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में हैं।

- सुकमा और मलकानगिरि जैसे जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी ने सुरक्षा तंत्र के संचार, सरकारी सेवाओं तक पहुँच तथा सामाजिक परिवर्तन को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के विस्तार ने उद्यमिता, डिजिटल वित्तीय सेवाओं तथा कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और लघु उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा दिया है।
- कनेक्टिविटी ने तथाकथित 'रेड पॉकेट्स' को अलगाव और दबाव की स्थिति से निकालकर संपर्क, समावेशन, राष्ट्रीय एकीकरण और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

नक्सल मुक्त भारत की दूरसंचार संबंधी प्रगति से पता चलता है कि कनेक्टिविटी शासन, सुरक्षा और विकास के बुनियादी ढाँचे के रूप में कार्य करती है।

8. पाँच दशक लंबे उग्रवाद का अंत करने वाला दृष्टिकोण

परिचय

31 मार्च, 2026 की घोषणा नक्सल-मुक्त भारत को केवल एक सुरक्षा सफलता के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक बहाली के रूप में चिह्नित करती है।

रणनीतिक संरचना और खुफिया तंत्र में बदलाव

- दंतेवाड़ा में 2010 में हुए हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे, जिससे वामपंथी उग्रवादियों के नियंत्रण की गहराई का खुलासा हुआ था।
- अपने चरम पर, माओवादी प्रभाव समानांतर प्रशासनिक ढाँचे के माध्यम से दस राज्यों के 223 जिलों में फैला हुआ था।
- गृह मंत्रालय की 2015 की नीति ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए संपूर्ण सरकारी सुरक्षा, विकास और समन्वय संरचना पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाया।
- जिला स्तरीय निगरानी प्रणालियों ने सीएपीएफ की तैनाती को सुव्यवस्थित किया, जिससे संघर्ष क्षेत्रों में एकीकृत कमान व्यवस्था का निर्माण हुआ।
- आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों से प्राप्त मानव खुफिया जानकारी ने माओवादी नेटवर्क की आंतरिक जानकारी को पूर्व-निवारक (Pre-emptive) अभियानों में रणनीतिक बढ़त में परिवर्तित किया।
- ड्रोन, सिग्नल अवरोधन और उपग्रह इमेजरी ने हमलों से पहले माओवादी इकाइयों की पहचान करने में मदद की।

परिचालन सफलता और सहकारी संघवाद पर आधारित समन्वय

- बस्तर और अबूझमाड़ में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का विस्तार हुआ, जिससे माओवादियों को जंगलों में शरण नहीं मिल पाई।
- सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, आईटीबीपी और राज्य पुलिस ने एक एकीकृत कमान संरचना का गठन कर समन्वित रूप से अभियान संचालित किए।
- हेलीकॉप्टर से रसद आपूर्ति, जासूसी तथा श्वान दस्तों के उपयोग से दुर्गम और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से अभियान चलाना संभव हुआ।
- जंगलों में सड़क निर्माण सुरक्षा बलों के लिए बलवर्धक और शासन की पुनर्स्थापना और विकास की वापसी का महत्त्वपूर्ण संकेत भी बना।
- वर्ष 2014 के बाद, केंद्र-राज्य समन्वय ने अधिकार क्षेत्र संबंधी टकराव को परिचालन जवाबदेही और साझा खुफिया जानकारी से परिवर्तित कर दिया दिया।
- छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों और राज्य पुलिस के क्षेत्रीय अनुभव को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की परिचालन क्षमता के साथ जोड़कर सहकारी संघवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा की एक प्रभावी शक्ति में परिवर्तित किया गया।

परिणाम, शेष चुनौतियाँ और शांति का एजेंडा

- मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव 223 जिलों से घटकर 20 से भी कम जिलों तक सीमित हो गया।
- राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 36 से घटकर 2025 में छह हो गई।
- सक्रिय वामपंथी उग्रवादी आंदोलन (एलडब्ल्यूई) की उपस्थिति दस राज्यों से घटकर तीन राज्यों तक सीमित हो गई, जिसमें लगभग 675 वामपंथी शेष रहे।
- वर्ष 2021-2026 के दौरान वामपंथी हिंसा में 70% से अधिक की गिरावट आई, जो विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुरक्षा दबाव को दर्शाती है।
- बस्तर, गढ़चिरौली और दक्षिणी झारखंड में शेष सक्रिय नेटवर्क के कारण वैचारिक पुनरुत्थान के खिलाफ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
- शांति के लिए केवल सैन्य सफलता ही नहीं, बल्कि सुशासन, वनाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समावेशी विकास और सामाजिक सहभागिता से ही सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष

नक्सल-मुक्त भारत केवल उग्रवाद पर विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन उपेक्षित और दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों, सुशासन और गरिमापूर्ण जीवन के माध्यम से राज्य की प्रभावी एवं विश्वासपूर्ण पुनर्स्थापना का द्योतक है।

9. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट

परिचय

इंडिया पोस्ट (भारतीय डाक) के जमीनी स्तर के नेटवर्क ने वामपंथी

उग्रवाद से प्रभावित दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों के मध्य शासन की पहुँच और विश्वास को मज़बूत किया।

डाक सेवाओं का विस्तार और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी

- इंडिया पोस्ट ने दूरस्थ एवं सेवाओं से वंचित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शासन और आवश्यक सेवाओं का विस्तार किया।
- शाखा डाकघरों ने उन क्षेत्रों में औपचारिक संचार संपर्क स्थापित किए जहाँ प्रशासनिक और बैंकिंग प्रणालियाँ कमजोर बनी हुई थीं।
- 2016-17 में 1,789 शाखा डाकघर स्थापित किए गए, जिससे अंतिम छोर तक संपर्क (First-Mile Connectivity) की आधारशिला रखी गई।
- वर्ष 2021-22 में 3,114 अतिरिक्त शाखा डाकघरों ने संवेदनशील क्षेत्रों में पहुँच को और मज़बूत किया।
- वर्ष 2024-25 में 294 शाखा डाकघरों ने समेकित लाभ और सतत विकास प्रयासों को प्रदर्शित किया।

वित्तीय समावेशन और राज्य के प्रति विश्वास

- शाखा डाकघरों द्वारा डाक सेवाएं, बचत, बैंकिंग, डीबीटी, बीमा और अन्य आधार-आधारित सेवाएँ प्रदान की।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने उन क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच का विस्तार किया जहाँ पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढाँचे की पहुँच सीमित थी।
- ग्रामीण डाक सेवकों ने स्थानीय जुड़ाव और मानवीय संपर्क प्रदान किया, जिससे संवेदनशील समुदायों में विश्वास का निर्माण हुआ।
- डाकघरों ने अलगाव को कम किया, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुगम बनाया और राज्य की प्रत्यक्ष उपस्थिति को मज़बूत किया।
- भारतीय डाक ने पत्रों और पार्सल सेवाओं से हटकर स्थिरता, अवसर और एकीकरण की ओर रुख किया।

निष्कर्ष

भारतीय डाक का वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में विस्तार यह दर्शाता है कि अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) केवल सेवा वितरण का माध्यम नहीं, बल्कि समावेशन, सुशासन और स्थायी शांति की आधारशिला है।

10. वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में लोकतंत्र की सुरक्षा

परिचय

31 मार्च, 2026 को घोषित वामपंथी उग्रवाद-मुक्त (LWE-free) स्थिति लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना का प्रतीक है, जिसमें पूर्व माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में राज्य की पूर्ण वापसी, नागरिक अधिकारों की पुनर्बहाली तथा गरिमापूर्ण जीवन की पुन:स्थापना सुनिश्चित हुई है।

क्षेत्रीय पुनर्प्राप्ति और लोकतांत्रिक सामान्य स्थिति

- 31 मार्च, 2026 की घोषणा के एक माह के भीतर ही जगदलपुर में 60 क्रिएटर्स के कार्यक्रम हुए, जो बस्तर में लोकतांत्रिक सामान्यता का स्पष्ट संकेत है।
- माओवादी जनता सरकार ने दंडकारण्य और रेड कॉरिडोर के पार समानांतर शासन के माध्यम से भारत के संविधान को चुनौती दी।
- पूर्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव तो हुए, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास की प्रभावशीलता सीमित बनी रही।
- वर्ष 2014 के पश्चात की रणनीति ने क्षेत्रीय नियंत्रण को बहाल किया, जिसे जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 से जुड़े एकीकरण और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के समानांतर देखा जाता है।
- राज्य ने क्लीयर-होल्ड-बिल्ड (Clear-Hold-Build) चरणों से आगे बढ़कर पूर्व में दुर्गम वन क्षेत्रों में दृश्य एवं वास्तविक लोकतांत्रिक उपस्थिति स्थापित की।

सुरक्षा दबाव और कैडर व्यवधान

- वर्ष 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे, जिससे वामपंथी उग्रवादियों के नियंत्रण की गहराई का खुलासा हुआ था।
- गृह मंत्रालय की 2015 की नीति ने अमित शाह के नेतृत्व वाली वामपंथी उग्रवाद विरोधी मुहिम को समन्वित संपूर्ण सरकारी कमान संरचनाओं के अधीन रखा।
- खुफिया तंत्र प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर मानव-खुफिया आधारित, ड्रोन-सक्षम और उपग्रह-समर्थित पूर्व-निवारक अभियानों की ओर अग्रसर हुआ।
- सुरक्षा शिविरों की संख्या बढ़कर 833 हो गई, जिनमें 2025 में 87 और 2026 में 16 नए शिविर स्थापित किए गए।
- वर्ष 2019 के बाद स्थापित 400 से अधिक शिविरों ने माओवादियों को सुरक्षित ठिकानों से वंचित कर दिया और दूरदराज के क्षेत्रों में सत्ता को बहाल कर दिया।
- आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या 2024 में 881 से बढ़कर 2025 में 2,337 हो गई जबकि इस वर्ष 700 से अधिक वामपंथियों ने आत्मसमर्पण किया।

विकास आधारित सेवा वितरण और विश्वास निर्माण

- विकास कार्यों ने सड़कों, कल्याणकारी सुविधाओं और सेवाओं को उन आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचाकर अलगाव की भावना को खत्म कर दिया, जहाँ पहले इन सुविधाओं की कमी थी।
- वर्ष 2024 के बाद वामपंथी क्षेत्र में सड़कों की लंबाई में 25% की वृद्धि हुई, जबकि 96 प्रतिशत गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्राप्त हुई।

- बैंक शाखाओं की संख्या 2014 में 3,320 से बढ़कर 2014 में 5,124 हो गई, जिससे लगभग 8,300 लोगों पर एक बैंक शाखा की पहुँच का स्तर प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2017-2026 के दौरान लगभग 6,000 डाकघर खोले गए, जिससे अंतिम छोर तक राज्य की उपस्थिति और मज़बूत हुई।
- स्थानीय जनजातीय भर्ती, बस्तर ओलंपिक, बस्तर पांडुम और चार गुना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के विस्तार ने लोकतंत्र को कल्याणकारी बनाया।
- बस्तर, गढ़चिरौली और दक्षिणी झारखंड जैसे क्षेत्रों में शेष सक्रिय नेटवर्कों के प्रति वैचारिक पुनरुत्थान को रोकने हेतु सतत सतर्कता आवश्यक बनी हुई है।

निष्कर्ष

यह परिवर्तन दर्शाता है कि सुरक्षा संबंधी लाभ तब स्थायी होते हैं जब उन्हें कल्याण, विश्वास और संवैधानिक लोकतंत्र में परिवर्तित किया जाता है।

11. बस्तर पांडुम

परिचय

बस्तर पांडुम उस क्षेत्र में सांस्कृतिक पुनरुत्थान को दर्शाता है जो डर से सामूहिक आत्मविश्वास की ओर बढ़ रहा है।

सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और जमीनी स्तर की भागीदारी

- बस्तर पांडुम 2026 ने मार्च अंत तक नक्सल-मुक्त भारत की दिशा में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक प्रस्तुत किया।
- यह ऋतु-आधारित जीवन-चक्र, प्रकृति से जुड़ी परंपराओं और सामुदायिक दृष्टिकोण के माध्यम से आदिवासी पहचान को व्यक्त करता है।
- 5 जनवरी से 9 फरवरी, 2026 तक आयोजित इस आयोजन में 32 विकास खंडों से 54,745 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- प्रतियोगिताएँ सात बस्तर जिलों और 1,885 ग्राम पंचायतों तक विस्तारित रहीं, जो व्यापक जमीनी सहभागिता को दर्शाती हैं।
- वर्ष 2025 का संस्करण, जो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसमें 47,000 कलाकारों ने भाग लिया और इसे गोल्डन बुक का दर्जा प्राप्त हुआ।
- इस आयोजन में श्रेणियों की संख्या सात से बढ़ाकर बारह कर दी गई, जिनमें संगीत, खान-पान, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान जैसे विविध क्षेत्र शामिल किए गए।

विकास, आजीविका और पुनर्एकीकरण

- सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ-साथ लगभग 40 वर्षों से बंद पड़े स्कूलों, सड़कों और मोबाइल टावरों का पुनर्निर्माण भी हुआ।
- बस्तर क्षेत्र में पाँच किलोमीटर के दायरे में डाकघरों और बैंक सुविधाओं की उपलब्धता ने अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को मज़बूत किया।
- 5 किलोग्राम चावल, ₹3,100 एमएसपी, रसोई गैस सिलेंडर और नल से जल जैसी सुविधाओं के विस्तार से घरेलू स्तर पर कल्याण में वृद्धि हुई।
- 118 एकड़ में प्रस्तावित औद्योगिक-ऑटो हब और 90,000 युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम जनजातीय रोजगार को लक्षित करता है।
- ₹3,500 करोड़ की रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना तथा ₹36 करोड़ की इंद्रावती परियोजना (120 मेगावाट क्षमता) ने क्षेत्रीय अवसंरचना और ऊर्जा उपलब्धता की संभावनाओं को बढ़ाया।
- पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को गरिमा प्रदान करते हुए हिंसक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया।

मान्यता, पर्यटन और शांति सुदृढ़ीकरण

- राष्ट्रीय स्तर पर बिरसा मुंडा जयंती और 150वीं वर्षगांठ के अवसर ने जनजातीय गौरव को व्यापक मान्यता प्रदान की।
- पंडित राम मांडवी, हेमचंद मांझी, अजय मांझी और बुधरी दाती को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- बस्तर में इको-सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत एडवेंचर टूरिज्म, होमस्टे, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी पहलें विकसित की गईं।
- 1,885 ग्राम पंचायतों में 55,000 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी ने सांस्कृतिक आधार पर जमीनी शांति-निर्माण को सशक्त किया।
- बस्तर पांडुम ने संघर्ष की पहचान को सांस्कृतिक जीवंतता, विकास की गति और सहभागी शासन में परिवर्तित कर दिया।

निष्कर्ष

बस्तर पांडुम यह दर्शाता है कि स्थायी शांति के लिए सुरक्षा, सांस्कृतिक पुष्टि, आर्थिक समावेशन और स्थानीय भागीदारी आवश्यक है।

12. शांतिपूर्ण समाज के लिए शांत मन

परिचय

एक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए केवल कानून, संस्थाएँ और विकास पर्याप्त नहीं हैं; इसके साथ-साथ भावनात्मक और मानसिक कल्याण भी आवश्यक है। योग जैसी प्राचीन भारतीय परंपराएँ व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता प्रदान कर सामाजिक शांति और संतुलन को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव

- मानसिक अशांति व्यक्तिगत कुंठा, अलगाव और क्रोध को व्यापक सामाजिक संघर्ष और असामंजस्य में बदल देती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लगभग आठ में से एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे तनाव संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।

- भारत में तनाव, चिंता, अकेलापन और मानसिक थकान वयस्कों, बच्चों और युवाओं को प्रभावित करते हैं।
- तीव्र जीवनशैली, सूचनाओं की भरमार और तुलना करने की प्रवृत्ति भावनात्मक असंतुलन और सहनशीलता में कमी करती है।
- मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है अनिश्चितताओं, दबावों और जीवन की अधूरी परिस्थितियों के बीच भी संतुलन, स्थिरता और आंतरिक संयम बनाए रखना।

आंतरिक संतुलन का योगिक मार्ग

- भगवद्गीता 2.48 में योग को समत्व के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कल्याण का मूल आधार है।
- योग सूत्र 1.2 योग को मानसिक उतार-चढ़ाव को शांत करने और आंतरिक स्पष्टता को बहाल करने के रूप में परिभाषित करता है।
- योग केवल शारीरिक आसनों या फिटनेस अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन, भावनाओं और व्यवहार का समन्वित एकीकरण है।
- प्राणायाम श्वास और मन की अशांति को नियंत्रित करता है, धीरे-धीरे संचित तनाव को दूर करने और शांति बहाल करने में मदद करता है।
- ध्यान और आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को अपने विचारों को प्रतिक्रियाओं में बदलने से पहले देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे आत्म-जागरूकता विकसित होती है।
- हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और NIMHANS के शोध तनाव कम करने और नींद में योग की भूमिका का समर्थन करते हैं।

सचेत समाज और भविष्य के लिए तैयारी

- सचेत जीवन का अर्थ है जागरूक उपभोग, धैर्यपूर्वक सुनना और सोच-समझकर कार्य करना, जिससे आवेगपूर्ण व्यवहार में कमी आती है।
- ईशा उपनिषद संयम सिखाता है, जो अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा, उपभोग और भावनात्मक निर्भरता का प्रतिकार करता है।
- भगवद्गीता के अध्याय 2, श्लोक 56 के अनुसार, स्थिर मन सुख-दुःख दोनों स्थितियों में समभाव बनाए रखता है।
- स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की रोकथाम के लिए भावनात्मक शिक्षा, योग और ध्यान की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने योग को मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए एक वैश्विक उपकरण बना दिया है।
- बृहदारण्यक उपनिषद अशांति से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रार्थना करता है।

निष्कर्ष

एक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए बाहरी प्रगति के साथ-साथ आंतरिक परिवर्तन भी आवश्यक है, जिससे भावनात्मक संतुलन सामाजिक सद्भाव का केंद्र बन जाता है।